

000 00000

जनसत्ता 05 जुलाई, 2014 : गंगा समग्र यात्रा के दौरान कनपुर में उमा भारती ने कहा था कि

उनकी पार्टी की सरकार बनने पर दो काम उनकी प्राथमिकता में होंगे। एक यह कि कनपुर के गंगा-जल के आचमन के योग्य बनाए जाएं और दूसरा, गौ हत्या पर कड़ी सख्त कानून बनाया जाए। लेकिन यहां हम बात केवल गंगा की कर रहे हैं। गंगा के लेकर बं-बं वादे करने वाले अब सत्ता में हैं।

कनपुर से ही बात शुरू करते हैं। इन पंक्तियों के लेखक का दावा है कि कनपुर में गंगा-जल है ही नहीं। तो फिर आचमन-योग्य किस चीज को बनाया जाएगा? कनपुर गंगा पथ का ऐसा अभाग शहर है जहां नाव पतवार से नहीं, बांस से चलती है। यहां की गंगा में तो टीबी अस्पताल के नाले जैसे कई नालों की गाद और टनिरिज का लाल-काला पानी है, जिसमें बांस गं-गं कर नाव के आगे बं-या जाता है। हरदिवार में आधे से ज्यादा गंगा-जल दिल्ली के पीने के लॉ-हर की पै-ी में डाल दिया जाता है। इसके बाद बजिनौर में मध्य गंगा नहर से भारी मात्रा में पानी संचाई के लॉ-ले लिया जाता है। बचा-खुचा पानी नरौरा लोअर गंग नहर में डाल कर उत्तर प्रदेश के हरति प्रदेश में पहुंचा दिया जाता है।

वास्तव में गंगा नरौरा में आकर ही खत्म हो जाती है। अदालत की लगातार फटकार और लोगों के दबाव में नरौरा के बाद बहुत थो-सा पानी आगे बं-ता है। नरौरा, जहां नहर नदी की तरह दिखाई देती है और नदी नहर की तरह- नाममात्र के इस गंगा-जल के कनपुर पहुंचने से ठीक पहले बैराज बना कर शहर के पानी पलाने के लॉ-रोकलिया जाता है। चूंकि शहर में पानी की क्लिलत रहती है इसलिए यहां से-कबूंद पानी भी आगे नहीं बं-पाता। इसके बाद इलाहाबाद के संगम में और बनारस की आस्था के स्नान में गंगा-जल के छो-कर सबकुछ होता है। वास्तव में आस्थावान लोग जिसमें गंगा समझ कर डुबकी लगाते हैं वह मध्य प्रदेश की नदियों- चंबल और बेतवा- का पानी होता है, जो यमुना में मलिकर गंगा के आगे बं-ता है। तो अगर नई सरकार का मन कनपुर में आचमन करने का है तो गंगा के वहां पहुंचाना होगा और उसके लॉ-ब-ी इच्छाशक्ति की जरूरत है।

नई सरकार आने के बाद से गंगा के लेकर नदी विकास की बातें प्रमुखता से कही गई हैं। तट विकास होंगे, पार्किंग बनेगी, घाट बनेंगे, पर्यटन को बं-वा देने के लॉ-लाइट ऐंड साउंड कार्यक्रम होगा, परविहन होगा, गाद हटाई जाएगी, मछली पालन भी होगा। लेकिन इस सब में मूल तत्त्व गायब है, गंगा में पानी कहां से आएगा इस पर कोई बात नहीं हो रही। जहाजरानी मंत्रालय की ओर से ग्यारह बैराज बनाने का विचार सामने आया है। इसकी सार्थकता पर सरकार के भीतर ही सवाल उठने लगे हैं। तो फिर क्या जाएगा ?

पहले कदम के रूप में नज्जी और उद्योगों के नालों के बंद करने का कदम उठाना चाहिए, ये नाले सरकारी नालों की अपेक्षा कफ़ी छोटे होते हैं लेकिन पूरे गंगा पथ पर इनकी संख्या हजारों में है। रही बात बं- और सरकारी नालों की, तो उन्हें बंद करने का वादा नहीं नीयत होनी चाहिए। वास्तव में उत्तरकशी,

हरदिवार, कनपुर, इलाहाबाद, बनारस और गाजीपुर जैसे शहरों की सीवेज व्यवस्था ही ऐसे डिजाइन की गई है, जिसमें गंगा मुख्य सीवेज लाइन का काम करती है। अब इन शहरों में पूरी सीवेज व्यवस्था के नए सरि से खर्च करना होगा ताकि गंगा इससे अछूती रहे। नए सीवेज सिस्टम के लिए बनारस भविष्य में एक मॉडल का काम कर सकता है।

वाराणसी के तीन पाइपलाइन मलिनी थी, पीने के पानी के अलावा वर्षाजल नकिसी और सीवेज की पाइपलाइन डाली जानी थी। शहर खोदा गया, सीवेज के पाइप डाले गए, लेकिन सीवेज संयंत्र के लिए जरूरी जमीन का अधग्रहण नहीं हो सका।

वाराणसी में हर रोज पैदा होने वाले चालीस करोड़ लीटर में लड़ी सीवेज में से मात्र सौ लीटर साफ हो पाता है, बाकी सारा गंगा के भेंट हो जाता है। सरकार के लिए वाराणसी की गलियों की ऐतिहासिकता बचा कर रखते हुए इस काम के कर पाना बड़ी चुनौती है।

दूसरा बेहद जरूरी कदम यह है कि कनपुर के चमई-करखानों के तुरंत वैकल्पिक जगह उपलब्ध कराई जाए। अदालत ने भी कई बार इन करखानों को हटाने का आदेश दिया है, लेकिन राजनीतिक इच्छाशक्ति न होने के चलते यह अब तक संभव नहीं हो सका। अक्टू उत्तर प्रदेश में 442 बं और मंडोले चमई करखाने हैं। जब सरकार चीन के बिजनेस पार्क के लिए जगह दे सकती है तो इन करखानों को क्यों नहीं?

तीसरा कदम है रविर पुलसिगि का। हर दो किलोमीटर पर एक गंगा चौकी हो, जहां जल-पुलसि की तैनाती हो, जिसमें स्थानीय मछुआरों को रोजगार दिया जाए। रविर पुलसि लोगों के गंगा में कचरा डालने से रोकेगी। अरथदंड लगाने जैसे अधिकार भ्रष्टाचार के बंधावा देंगे, इसलिए रविर पुलसि की भूमिका जागरूकता पैलाने और स्थानीय प्रशासन के बीच सेतु बनाने की होनी चाहिए।

गंगा संरक्षण की दृष्टि में चौथा उपाय मोटर से चलने वाली छोटी नाव पर रोक के रूप में होना चाहिए। रोजगार के नाम पर लाखों की संख्या में डीजल आधारित मोटरबोट गंगा में चलती हैं। नावों में लगाई जाने वाली ये सेक्वेंस मोटर्स बड़ी संख्या में बांग्लादेश से तस्करी कर लाई जाती हैं। अत्यधिक पुरानी होने के चलते इनसे काला धुआं और तेल की परत निकलती है, जिसमें मछलियां और उनके अंडे जीवित नहीं रह पाते। इन नावों में डीजल की जगह केरोसिन का उपयोग होता है। एक तरह का दूध दिया जाता है कि जब छोटे जहाज और स्टीमर गंगा में चल सकते हैं तो इन गरीबों की नाव रोकने की क्या तुक है। पर गंगा में स्टीमर और फेरी मुख्यतः बिहार और बंगाल में ही चलते हैं जहां गंगा में पानी की समस्या नहीं है। बनारस तक के क्षेत्र में, जहां गंगा अस्तित्व के लिए ही जूझ रही है, वहां यह बंद होना चाहिए। वहां गैस से चलने वाले स्टीमर की इजाजत दी जा सकती है।

पांचवां और बेहद महत्वपूर्ण विषय है आस्था के ठेस पहुंचाना। बिना पूजन सामग्री के नपिटान का गंगा पथ पर बसे घरों की समस्या यह है कि वे पूजा के फूलों और पूजन सामग्री का क्या करें। मजबूरी में लोग उसे नदी में डालते हैं, क्योंकि वहीं और फेंकने से आस्था के ठेस पहुंचती है। एक उपाय यह है कि हर रोज नगर नगिम इस पूजन सामग्री के लोगों के घरों से इकट्ठा करें। इस काम के लिए कृषि उठाने वाली गांवियों का उपयोग न किया जाए। इस इकट्ठा की गई पूजन सामग्री का उपयोग खाद बनाने में हो सकता है। मूर्ता विसर्जन पर पूर्णतः रोकछठा कदम है, जिसके लिए दृष्टि इच्छाशक्ति चाहिए। सातवां नरिण्य तुरंत लागू किया जा सकता है, कि मौजूदा सीवेज शोधन संयंत्र अपनी पूर्ण क्षमता से काम करें। अभी तो आधे से भी कम संयंत्र चालू हालत में हैं, ये भी अपने दावे के अनुरूप नहीं चलते। सिर्फ उत्तर प्रदेश में पैतालीस बंधाले गंगा में गरिते हैं, छोटे नालों की तो गिनती ही नहीं है। अक्टू बनारस में तीस छोटे-बंधाले गंगा में मलिते हैं। बिजली की भारी कमी के चलते भी सीवेज प्लांट नहीं चलते।

यह हालत खासकर उत्तर प्रदेश में है जहां इन संयंत्रों का चालू रहना बेहद जरूरी है। साथ ही यह पक्का किया जा कि भविष्य में कोई नया प्लांट नहीं लगाया जागा। हमारे देश की स्थिति लंदन से अलग है। हमारे यहां सीवेज जमीन के भीतर नहीं इकट्ठा होता जसि शोधति कर उपयोग में लाया जा सके। हमारे यहां तो बहते हु नालों के ही सीवेज ट्रीटमेंट सेंटर बनाने की जरूरत है और उस शोधति पानी के भी गंगा में या सचिाई में उपयोग में न लाया जा। कबानगी देखी। वाराणसी केपास सारनाथ से सटे केटवा गांव में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया। पहले पहल शहर केगंदे नाले का पानी खेतों में डाला गया तो लगा दूसरी हरति क्रांति हो गई। फसल चार से दस गुना तक बढ़ी।

मगर अब स्थानीय लोग खुद इन खेतों की सब्जियों के हाथ नहीं लगाते, क्योंकि वे देखने में तो चटकहरी, बनी और सुंदर होती है मगर उनमें कोई स्वाद नहीं होता, और कुछ ही घंटों में की प जाते है। यही हाल अनाज का भी है, सुबह की रोटी शाम के खाइ तो बदबू आगी। कई सालों तक उपयोग करने केबाद बी चयू के अध्ययन में यह सामने आया कि शोधति पानी सोने की शकल में जहर है। इन साग-सब्जियों में वैटमियम, नकिलि, क्रोमियम जैसी भारी धातु पाई जाती है।

लोक्त्तुभावन घोषणाओं और गंभीर पहल केबीच का फरक समझते हु उमा भारती के अगले कदम केरूप में हरदिवार और ऋषकेश के आश्रमों के नोटसि देना चाहती। कि वे क समय-सीमा के भीतर अपने सीवेज का वैक्त्पकि इंतजाम कर लें। इनके भक्तों पर गंगा के नरिमल बनाने और नरिमल रखने की इनकी अपील का असर तब पगा, जब ये खुद इस पर अमल करेंगे। अब तकतो गंगा आंदोलन में शामिल सभी आश्रमों के मुंह से नरिमल गंगा की बात ऐसे ही लगती है जैसे हम पे कटते है, उसका कगज बनाते है और फिर उस पर लिखते है 'वृक्ष बचाओ'।

अवरिल गंगा केरास्ते की बाधा हटाने का नौवां कदम होना चाहती। हर बैराज केठीकपहले डसिलिटिंग का गंगा पर बने हर बैराज केपहले कई किलोमीटर तक भारी गाद जमा हो गई है; फरक्का बैराज केपहले जमा गाद ने गंगा की सहायकनदियों पर भी काफी प्रतक्विल प्रभाव डाला है। साथ ही गंगा में रेत खनन पर जारी रोकके तुरंत हटाना चाहती। रेत खनन न होने से कई जगह नदी का स्तर उठ गया है, जो आने वाले मानसून में बा का सबब हो सक्ता है। रेत खनन वशिषज्ज की देखरेख में किया जा, क्योंकि गाद हटाने केनाम पर रेत माफिया कब से गंगा पर नजर गी। हु है। वास्तव में यह रेत खनन नहीं रेत चुगान होना चाहती। बालू केक्षेत्र के नयित्त्रति किया जाना जरूरी है।

दसवां और सबसे महत्त्वपूर्ण काम गंगा में गंदगी डालने के कर्बन क्रेडिट जैसा मामला नहीं बनाना चाहती। किसी भी उद्योग पर गंदगी डालने पर जुर्माना न लगाया जा, हर हाल में यह पक्का करना चाहती कि गंदगी न डाली जा, जुर्माने वाली व्यवस्था से सरिफ भ्रष्टाचार के ब। वा मलिता है। कई ब उद्योगों का गणति यह है कि जुर्माना देना सरल है, वैक्त्पकि व्यवस्था करना महंगा है। इसल। वे जुर्माने के मलबा नपिटान की अपनी लागत में जो का चलते है।

कप्यारी छोटी-सी मछली होती है हलिस। फरक्का बनने से पहले वह गंगा में ही पाई जाती थी। खारे पानी की यह मछली अंडे देने मीठे पानी में उत्तराखंड तक आती थी। कनपुर का जल आचमन केलायकहुआ या नहीं, इस पर वैज्ञानिक बहस करते रहेंगे। पर जसि दिन कनपुर में हलिसा नजर आई, समझें वह नई मंत्री का इस्तकमाल करने आई है। क्या न शासन में इतनी इच्छाशक्ती है?

फेसबुक पेज को लाइक करने के लिए क्लिक करें- <https://www.facebook.com/Jansatta>

ट्विटर पेज पर फॉलो करने के लिए क्लिक करें- <https://twitter.com/Jansatta>